पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या-8229

में

2024 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या-286

==========

1. मेसर्स रीता पेट्रोल पंप अपने मालिक गोपाल कुमार झा के माध्यम से, जिसका स्थान-रामचंद्रपुर, थाना-सरायरंजन, जिला समस्तीपुर, मुसापुर सरायरंजन, थाना-घाथो, जिला-समस्तीपुर।

2. गोपाल कुमार झा, पुत्र-स्वर्गीय दिवाकरा झा, निवासी-गाँव-मुसापुर, सरायरंजन, थाना-घाथो, जिला समस्तीपुर।

.....अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कार्यालय राज्य प्रमुख के माध्यम से आशियाना टावर, पहली मंजिल, प्रदर्शनी रोड, पटना में है।

2. राज्य प्रमुख, आशियाना टावर, पहली मंजिल, प्रदर्शनी रोड, पटना।

3. क्षेत्र प्रबंधक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरौनी।

4. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्तीपुर।

5. प्राचार्य, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मणियारपुर, विद्यापति नगर, समस्तीपुर।

6. हेमंत कुमार प्रसाद, प्राचार्य, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, मणियारपुर, विद्यापति नगर, समस्तीपुर।

.....उत्तरदातागण/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्रीमती निवेदिता निर्विकार, वरिष्ठ अधिवक्ता
सुश्री सुप्रज्ञा, अधिवक्ता

		श्री अभिषेक सिंह, अधिवक्ता
		श्री सुमित कुमार, अधिवक्ता
		श्री नीरज कुमार अधिवक्ता
		श्री साहिल कुमार, अधिवक्ता
बीपीसीएल के लिए	:	श्री संजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री सिद्धार्थ प्रसाद, अधिवक्ता
		श्री ओम प्रकाश कुमार, अधिवक्ता
		श्री सुमित कुमार, अधिवक्ता
		श्री रुद्रांक शिवम सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री सर्वेश कुमार सिंह, एएजी-13
		श्री आर्य अचिंत, एसी से एएजी-13
		श्री अभिनव आलोक, एसी से एएजी-13

==========

सरकारी ठेका—डीलरशिप की समाप्ति—अपीलकर्ता को तीसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जो पहले के कारण बताओ नोटिस के समान था—विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के बाद तीसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था—इससे पहले कॉर्पोरेशन द्वारा दोनों कारण बताओ नोटिस वापस ले लिए गए थे—कार्यवाही स्पष्ट रूप से मनमानी है और कॉर्पोरेशन की कार्रवाई प्रकृति में प्रतिशोधी है—वर्ष 2016 में किए गए आवंटन को रद्द नहीं किया जा सकता है, और आरोप संधारणीय/टिकाऊ/संपोषणीय नहीं हैं—कॉर्पोरेशन को 2016 के आवंटन के संबंध में कोई और कदम उठाने से रोका गया क्योंकि या तो निर्भरता उचित नहीं है या निर्भरता का प्रमाण पत्र वैध नहीं है—रिट याचिका अनुज्ञात किया गया; और कॉर्पोरेशन के प्रतिशोधी रवैये के कारण कॉर्पोरेशन पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया।

(पैरा 28 से 34)

*सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला 8229/2020—**अपास्त किया गया***

*2018 (4) पी.एल.जे.आर. 993—**संदर्भित किया गया***

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश
एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार

सीएवी निर्णय

(प्रतिः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख: - 29.04.2024

अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का विरोध किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रतिवादी-निगम ने तत्काल रिट याचिका में पारित किए गए 06.10.2020 और 07.02.2023 दिनांकित आदेशों को दरकिनार करते हुए डीलरशिप को समाप्त करने का आदेश पारित किया; लेकिन हालाँकि प्रतिवादी-निगम को कार्रवाई के उसी कारण पर एक नया कारण-सूचना जारी करने की स्वतंत्रता छोड़ दी गई।

2. विद्वान वरिष्ठ वकील श्रीमती निवेदिता निर्विकर ने बताया कि जारी किए गए दो कारण दर्शाओ नोटिसों के खिलाफ रिट याचिका में ली गई दलीलों पर विचार नहीं किया गया। यदि जारी किया जाता है तो एक नया कारण-बताओं सूचना उसी कार्रवाई के कारण होगा, जिसे निगम के समक्ष नए सिरे से आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निगम ने बार-बार कारण- बताओं सूचना द्वारा अपीलार्थी को पेट्रोल पंप के आवंटन को किसी तरह रद्द करने के लिए अपने पूर्वाग्रहपूर्ण दिमाग का खुलासा किया है, जो आवंटन वर्ष 2014 के एक विज्ञापन के अनुसार वर्ष 2016 में भी था। अब तक इस अपील में तीसरा कारण-बताओं सूचना जारी किया गया है, जो समान तथ्यों और पहले के सूचना के शब्दशः प्रतिलिपि पर है। आवंटन, जिसे रद्द करने की मांग की गई थी, अपीलार्थी को एक सरकारी कर्मचारी के आश्रित के रूप में किया गया था, उस विद्यालय के प्रचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा मृत्यु के आधार पर जारी प्रमाण पत्र जिसमें अपीलार्थी के पिता कार्यरत थे। उस समय, निगम ने विद्यालय के प्राचार्य से प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ इसकी वास्तविकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था; जिसकी पुष्टि प्राचार्य द्वारा की गई थी, जिसके आधार पर वर्ष 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया था। अपीलार्थी बिना

किसी शिकायत के पेट्रोल पंप पर सफलतापूर्वक काम कर रहा था जब निगम ने खुदरा दुकानों के आवंटन के लिए दूसरा विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने भी उसी निर्भरता खंड के आधार पर आवेदन किया।

3. वर्ष 2018 के विज्ञापन से एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें प्राचार्य से वर्ष 2019 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस उदाहरण में, यह पाते हुए कि अपीलार्थी के पिता की मृत्यु की तारीख रविवार थी, निगम ने जिला शिक्षा अधिकारी (डी. ई. ओ.) से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या उसके पित्ता उक्त दिन ड्यूटी पर थे। अपीलार्थी ने बी. पी. सी. एल. के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई और बी. पी. सी. एल. ने दो पहलुओं पर गौर करने के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया; एक यह कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है और क्या अपीलार्थी के पिता का वास्तव में सेवा में रहते हुए निधन हो गया है; जैसा कि दावा किया गया है। डी. ई. ओ. ने समिति को सूचित किया कि अपीलार्थी के पिता का निधन सेवा में रहते हुए हो गया, जबकि स्कूल के प्राचार्य ने एक पत्र जारी किया कि अपीलार्थी के पिता उनकी मृत्यु की तारीख को ड्यूटी पर नहीं थे। डी. ई. ओ. द्वारा एक और स्पष्टीकरण जारी किया गया था जिसमें संकेत दिया गया था कि याचिकाकर्ता के पिता की सेवा के दौरान मृत्यु नहीं हुई थी; क्योंकि 23.09.1984 रविवार था और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ग्राम पंचायत के पंजीयक हैं।

4. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, अपीलार्थी को दिनांक 29.08.2020 के अनुलग्नक-ए 4 के रूप में प्रस्तुत एक कारण बताओं सूचना जारी किया गया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की थी, जिसमें दिनांक 06.10.2020 के आदेश द्वारा, निर्देश जारी किए गए थे; अपीलार्थी को कारण-बताओं सूचना का जवाब देने के लिए, प्रत्यर्थियों को एक जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए और इस बीच कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने के लिए। उत्तरदाताओं द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था और 21.12.2020 पर, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने बीपीसीएल द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दिया कि बिहार सेवा संहिता के नियम 184 के अनुसार, छुट्टियों को भी सेवा की अवधि माना जाता है। 13-01-2021 को फिर से, इस न्यायालय ने मामले में उत्पन्न होने वाले प्रासंगिक मुद्दों को उठाया कि क्या रविवार को मृत्यु को सेवा पर मृत्यु के रूप में माना जा सकता है और अंतरिम आदेश को जारी

रखने का निर्देश दिया। 15.01.2021 और बाद में 15.01.2022 पर, कारण बताओं सूचना वापस ले लिया गया।

5. बी. पी. सी. एल. ने फिर से अपीलार्थी के प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए डी. ई. ओ. से संपर्क किया और 27.08.2022 पर, विद्यालय के प्राचार्य ने एक संचार जारी किया जिसमें कहा गया कि जारी किया गया प्रमाण पत्र विद्यालय के अभिलेख में उपलब्ध नहीं था और अभिलेख से जो देखा जाता है वह यह है कि संचार हस्ताक्षर सत्यापन के लिए जारी किया गया था। 07-10-2022 को एक दूसरा कारण-बताओं सूचना इस आधार पर जारी किया गया था कि अपीलार्थी अपने पिता की मृत्यु के चार महीने बाद पैदा हुआ था और इसलिए निर्भर नहीं था; आगे जालसाजी का आरोप लगाते हुए क्योंकि प्राचार्य ने प्रस्तुत किया था कि जारी किया गया संचार एक हस्ताक्षर सत्यापन था न कि निर्भरता प्रमाण पत्र। इसके बाद, अपीलार्थी ने 2022 का आई. ए. सं. 2 दायर किया ताकि विद्यालय के प्रधानाचार्य को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में शामिल किया जा सके और दूसरे कारण बताओं सूचना के साथ-साथ प्रधानाचार्य के पत्र को भी रद्द किया जा सके। अपीलार्थी ने मूल दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए विद्यालय के अभिलेखों को प्रस्तुत करने की भी मांग की। निगम ने 2022 का आई. ए. सं. 3 दायर किया, जिसमें 29.08.2020 के कारण- बताओं सूचना को वापस लेने और रिट याचिका को ही बंद करने की मांग की गई।

6. रोस्टर परिवर्तन के कारण, मामले को एक खंड पीठ के समक्ष रखा गया, जिसने 2022 की आई. ए. संख्या 2 को अनुमति दी और दायर की याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित 07.02.2023, लेकिन बाद में बीपीसीएल द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करते हुए 09.02.2023 पर एक समाप्ति पत्र जारी किया गया था। प्रयास केवल इस न्यायालय द्वारा एक परीक्षा को दरकिनार करने के लिए था कि क्या रद्द करना उचित था। यह मुद्दा कि क्या अपीलार्थी वर्ष 2016 में पेट्रोल पंप आवंटित किए जाने का हकदार था, अब जीवित नहीं है और इसे रद्द करने का कोई आधार नहीं है। केवल इसलिए कि उसी आधार पर एक आवेदन द्वारा मांगे गए दूसरे आवंटन को अस्वीकार कर दिया गया था, निगम को पहले के आवंटन को रद्द करने में सक्षम नहीं बनाएगा जो उचित सत्यापन के बाद किया गया था।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय सिंह प्रतिवादी-निगम की ओर से पेश होते हैं और बताते हैं कि निगम द्वारा दूसरा आवंटन देने से इनकार करने के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की गई थी; जिसे वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था, लेकिन एक लागत के साथ। अपीलार्थी ने उससे कोई अपील दायर नहीं की और विभिन्न अधिकारियों से शिकायत करते रहे। दूसरे आवेदन के अनुसार आवंटन से इनकार इस निष्कर्ष पर था कि अपीलार्थी निर्भरता खंड के तहत आवेदन करने का हकदार नहीं था, जो वह आधार था जिसके आधार पर पहला आवंटन किया गया था। इसने पहले आवंटन के रूप में भी गंभीर मुद्दों को जन्म दिया, जिस परिस्थिति में, पहले आवंटन को रद्द करना पूरी तरह से क्रम में था। विद्वान वरिष्ठ वकील हमें अनुलग्नक-15 दिनांक 09.12.2014 पर ले गए जो पहली बार में प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र है, जिसकी वास्तविकता पर जिला शिक्षा अधिकारी के जवाबी हलफनामे के साथ प्रस्तुत अनुलग्नक 8 द्वारा गंभीर रूप से संदेह किया गया है। यह इंगित किया गया है कि अपीलार्थी अपने पिता की मृत्यु के समय पैदा नहीं हुआ था और जारी किए गए प्रमाण पत्र में अपीलार्थी को मृतक के आश्रित के रूप में दिखाया गया है, जो दस्तावेज़ के सामने झूठा और धोखाधड़ी वाला दावा है।

8. **सद्भावना एच. पी. गैस बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2018 (4) पी. एल. जे. आर. 993** पर भी भरोसा रखा गया था। अपीलार्थी जानबूझकर गलत अभ्यावेदन का दोषी है। निगम द्वारा जारी विवरणिका, जिसमें खुदरा दुकानों के आवंटन के लिए आवेदनों का आह्वान किया गया है, स्पष्ट रूप से किसी भी स्तर पर आवंटन को रद्द करने के लिए प्रदान करता है जब यह स्थापित हो जाता है कि आवंटन आवेदक द्वारा किए गए गलत अभ्यावेदन के कारण गलत आधार पर था। प्रतिवादी-निगम का तर्क है कि यक घिसा-पिटा सिद्धांत है कि धोखाधड़ी हर चीज को दूषित करती है, जो अपील को खारिज करने की मांग करता है।

9. हम सबसे पहले उस निर्भरता खंड को देखेंगे जिसके तहत याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था, जो निम्नांकित हैः-

घ) **सरकार (पी. एम. पी. सहित) और सार्वजनिक क्षेत्र कार्मिक**

केंद्रीय/राज्य के विभिन्न विभागों में सेवारत कार्मिक। केंद्र/राज्य सरकार की सरकारें और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अक्षम या अक्षम हैं, वे इस

श्रेणी के तहत पात्र होंगे। मृत्यु के मामले में, कर्तव्यों का पालन करते समय, उनकी विधवाएँ/आश्रित इस श्रेणी के तहत पात्र होंगे।

*इस श्रेणी के तहत आवेदकों को कार्यालय के प्रमुख या सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संबंधित संगठन/सरकारी विभाग से प्रासंगिक प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करनी चाहिए-परिशिष्ट **VIII***

10. उपरोक्त खंड (घ) के दो अंग हैं, एक, उन व्यक्तियों को दिया जाने वाला लाभ जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अक्षम या विकलांग थे और दूसरा, जो सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों के आश्रितों को दिया जाता है, जिनकी कर्तव्यों का पालन करते हुए मृत्यु हो गई थी। इस श्रेणी के तहत आवेदनों को कार्यालय के प्रमुख या सरकार के अवर सचिव के पद से कम के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संबंधित संगठन/सरकारी विभाग से संबंधित प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ भी संलग्न किया जाना चाहिए। जैसा कि हम समझते हैं कि इसका लाभ सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उस कर्मचारी को मिलता है जो विकलांग होने के कारण अपनी नौकरी खो देता है और जो कर्मचारी काम पर रहते हुए मर जाते हैं, उनके आश्रितों को मिलता है। विकलांग कर्मचारी को उसके रोजगार के नुकसान के कारण और मृतक कर्मचारी के आश्रितों को, परिवार के कमाने वाले को खोने के कारण, पेट्रोलियम उत्पादों के एक खुदरा आउटलेट का आवंटन करके आय/आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत दिया जाता है; सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी एक प्रशंसनीय उद्देश्य। जाहिर है, एक विकलांग कर्मचारी जिसे किसी अन्य श्रेणी या अतिरिक्त पद पर अक्षमता के बावजूद रोजगार में बने रहने की अनुमति है, वह तेल कंपनी का खुदरा आउटलेट चलाने का हकदार नहीं होगा।

11. पहली बार में, निर्भरता खंड को पूरी तरह से डाइंग-इन-हार्नेस योजना के समान नहीं कहा जा सकता है। फिर भी, हम इस बात पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकते कि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मृत्यु या अक्षमता की स्थिति को सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी सेवाओं में शामिल नहीं किया जा सकता है। कर्तव्यपालन के दौरान मृत्यु उन मामलों में होगी जहां कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, सेवा की प्रकृति या अपने कर्तव्यों के कारण कुछ खतरनाक गतिविधिय की जाती हैं। सशस्त्र बलों या पुलिस या कानून और व्यवस्था के रखरखाव या विघटनकारी गतिविधियों की रोकथाम में लगे ऐसे किसी भी बल

का सदस्य सेवाओं के उदाहरण होंगे, जो अपने स्वभाव से ही खतरनाक है। एक खतरनाक विनिर्माण गतिविधि एक कर्तव्यों का उदाहरण होगा, जिससे अंग या जीवन की हानि हो सकती है। चूंकि यह धारा विद्यमान है, इसे इस रूप में समझा जाना चाहिए कि यह धारा, परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण विकलांगता या निर्भरता की हानि के कारण रोजगार के नुकसान की स्थिति में खुदरा दुकान के आवंटन का अधिकार देती है; जिससे कर्मचारी या उसके परिवार को आजीविका के नुकसान और संभवतः घोर गरीबी का सामना करना पड़ता है। आजीविका और संभवतः घोर गरीबी। इसलिए, व्यापक परिप्रेक्ष्य में एक लाभकारी खंड के रूप में समझा जाता है; विशेष रूप से जब सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के पूरे वर्ग को इसके दायरे में लाया जाता है; जो किसी ऐसे रोजगार तक सीमित नहीं है जो अपनी प्रकृति से ही खतरनाक या जोखिमपूर्ण है, तो इसे एक ऐसी योजन के समान माना जाना चाहिए जो मृत्यु काल में समाप्त हो जाए । अक्षमता या मृत्यु के कारण आजीविका का नुकसान यह जांचने में प्रचलित विचार होगा कि क्या विशिष्ट खंड के तहत एक आवेदक को पात्रता है या नहीं।

12. एक विद्यालय के शिक्षक या विद्यालीय के एक कर्मचारी की यदि सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु को शायद ही कभी किए गए कर्तव्यों की कठिन प्रकृति के कारण कहा जा सकता है; जो कर्तव्य किसी भी कारण से अपने स्वभाव से खतरनाक या जोखिमपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। नौकरी में रहते हुए परिवार को गरीबी में डालने वाली मृत्युः वह संदर्भ है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी, निगम द्वारा उपरोक्त लाभकारी खंड द्वारा शमन की पेशकश की जाती है जो विकलांग कर्मचारी या मृत कर्मचारी के आश्रितों के लिए एक जीवन रेखा प्रदान करता है। लाभकारी खंड को सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों और उनके आश्रितों की आजीविका के इस तरह के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है; निगम को दिए गए सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में।

13. इस संदर्भ में, हमें ध्यान देना होगा कि दूसरे कारण बतओं सूचना में आरोप लगाया गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता का जन्म अपने पिता की मृत्यु के चार महीने बाद हुआ था, इसलिए उसे आश्रित नहीं कहा जा सकता है; जिसे हम काफी तुच्छ और अतार्किक पाते हैं। गर्भ में एक बच्चा अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है और केवल इसलिए कि वह पिता के जीवनकाल में पैदा नहीं हुआ था, इससे माता-पिता से उत्पन्न दावों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा; चाहे वह मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकार हो या आश्रितों के लिए उपलब्ध लाभकारी योजनाएं,

जैसे कि डाइंग-इन-हार्नेस योजना। अनुकंपा आधारित रोजगार निश्चित रूप से तभी फलीभूत हो सकता है जब आश्रित बच्चा वयस्क हो जाए, और वह भी योजना की शर्तों के अनुसार ही होना चाहिए। निगम द्वारा शुरू की गई लाभकारी आबंटन योजना कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है; कई योजनाओं की तरह जो मृत्यु-काल में रोजगार को हानि होने के कुछ वर्षों के भीतर ही सीमित कर देती हैं । विषय खंड में केवल सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों पर निर्भरता की आवश्यकता होती है, जिनकी कर्तव्यों का पालन करते हुए मृत्यु हो गई थी। गर्भ में एक बच्चा, जो पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है, उसका पिता की संपत्ति पर उतना ही दावा होता है जितना कि मृत्यु से पहले पैदा होने वाले किसी भी बच्चे का होता है और उसे गर्भ में रहते हुए और उसके जन्म के बाद भी निर्भरता का नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह, की एक लाभकारी योजना के लिए दावा किया जाएगा। जैसे कि मृत्युदंड योजना या अधिमान्य आवंटन जो इस अपील का विषय है।

14. मान लीजिए, समस्तीपुर में पेट्रोल और डीजल में खुदरा दुकान के पुरस्कार के लिए पहला विज्ञापन, वह भी आरक्षित श्रेणी में, 09.10.2014 पर जारी किया गया था, जैसा कि जवाबी हलफनामे में प्रस्तुत अनुलग्नक-ए से देखा जाता है। अपीलार्थी ने अनुलग्नक प्रस्तुत करते हुए निर्भरता खंड के तहत आवेदन किया था -1. अनुलग्नक-1 दिनांक 09.10.2014 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, मनियारपुर ब्लॉक, विद्यापीठ नगर, जिला-समस्तीपुर से जारी किया गया है। यह प्रमाणित करता है कि एक सहायक शिक्षक के रूप में विद्यालय में काम करने वाले दिवाकर झा का स्कूल में ड्यूटी के दौरान 23.09.1984 पर निधन हो गया। यह भी कहा गया है कि विद्यालय के अभिलेख के अनुसार, अपीलकर्ता स्वर्गीय दिवाकर झा का आश्रित है। अब भी इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अनुलग्नक-1 प्रमाण पत्र में पढ़े गए तथ्य झूठे या मनगढ़ंत हैं। अपीलकर्ता दिवाकर झा का बेटा है और दिवाकर झा की मृत्यु 23.09.1984 पर हुई, जब यह एक सहायक शिक्षक के रूप में एक सरकारी विद्यालय, की सेवा में थे। अनुलग्नक-1 के विरुद्ध विवाद इस आधार पर है कि विद्यालय के अभिलेखों में पुत्र, अपीलार्थी, जो मृत्यु के समय पैदा नहीं हुआ था, की पहचान प्रकट करने का कोई कारण नहीं था। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि पिता की मृत्यु के तुरंत बाद लगभग चार महीने के भीतर अपीलार्थी का जन्म हुआ था, जैसा कि काउंटर एफिडेविट में अनुलग्नक-बी के रूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र में जन्म तिथि से स्पष्ट है। इसलिए जब उनके पति की मृत्यु हुई तब अपीलार्थी की

माँ शायद गर्भावस्था में छह महीने की थीं। परिवार के कारण सेवानिवृत्ति लाभ होते जिनके लिए स्कूल में कागजात जमा किए जाते और इसमें अपीलार्थी को मृत सहायक शिक्षक के बेटे के रूप में भी दिखाया जाता। उल्लेखनीय है कि प्रमाण पत्र 1984 में मृत्यु के तुरंत बाद जारी नहीं किया जाता है, बल्कि मृत्यु के तीन दशकों के बाद जारी किया जाता है; वर्ष 2014 में।

15. निगम ने स्वयं अनुलग्नक-14 दिनांक 26.06.2015 के साथ दिनांक 04.01.2021 के पूरक हलफनामे के साथ यह स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या प्रमाण पत्र वास्तव में प्रचार्य के कार्यालय से जारी किया गया था और क्या यह वास्तविक था। यह इस तरह की पुष्टि के अनुसार था कि रिट याचिका में प्रस्तुत अनुलग्नक-2 पर अपीलार्थी को पेट्रोल पंप आवंटित करते हुए जारी किया गया था। अपीलार्थी खुदरा दुकान का संचालन जारी रखे हुए था और दुकान के संचालन में अब तक उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई है। निगम द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के खिलाफ उचित पूछताछ की गई थी और पुष्टि प्राप्त करने के बाद ही, खुदरा आउटलेट के आधार पर आवंटित किया गया था। निर्भरता खंड।

16. यह भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि जारी किया गया प्रमाण पत्र प्राचार्य द्वारा था जो उस विद्यालय के प्रमुख थे जिसमें अपीलार्थी के पिता काम कर रहे थे। डी. ई. ओ. का बाद में स्पष्टीकरण कि केवल स्थानीय निकाय ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि निगम के विवरणिका में शामिल निर्भरता खंड के लिए केवल कार्यालय प्रमुख से एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जिसमें मृतक सेवारत था, जो कि तत्काल मामले में एक स्कूल होने के नाते, यह स्पष्ट रूप से प्राचार्य होगा। मृत्यु के संबंध में स्थानीय निकाय से जारी प्रमाण पत्र की कोई मांग नहीं की गई थी और न ही उस विशिष्ट तिथि के बारे में कोई सत्यापन किया गया था जिस पर मृत्यु हुई थी, छुट्टी या कार्य दिवस होने के नाते। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, भले ही यह एक कार्य दिवस था, एक सहायक शिक्षक की स्थिति में रोजगार होने के कारण, मृत्यु के कर्तव्यों के निर्वहन का प्रत्यक्ष कारण होने की बहुत कम गुंजाइश है। निर्भरता खंड में यह भी आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कर्तव्यों के निर्वहन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में हो, लेकिन यह केवल कर्तव्यों के दौरान होने की आवश्यकता है।

17. इस संदर्भ में, हम निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा प्रस्तुत अनुलग्नक- 13 पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकते हैं, जिसने का जवाब दिया। निगम द्वारा यह स्पष्टीकरण देने के लिए कि बिहार सेवा संहिता के नियम 184 के अनुसार छुट्टी की अवधि को भी शुल्क माना जाता है। यह वह संचार है जिस पर दिनांक 15.01.2022 के अनुलग्रक-27 में भरोसा किया गया है; जिसके कारण 29.08.2020 पर जारी किया गया पहला कारण बतओं सूचना वापस ले लिया गया। छुट्टियों, विशेष रूप से रविवार को वेतन के भुगतान के लिए भी कर्तव्य के रूप में माना जाता है और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जैसा कि नियम 184 में देखा गया है, ड्यूटी पर बना रहता है, चाहे वह छुट्टी हो या स्वीकृत छुट्टी। यह कि 23.09.1984 रविवार था, उस समय निगम द्वारा आसानी से सत्यापित किया जा सकता था जब आवंटन किया गया था। रविवार को हुई मृत्यु के बारे में कोई आपत्ति नहीं की गई थी, जब अपीलार्थी को खुदरा दुकान आवंटित करने के लिए निर्भरता खंड का आह्वान किया गया था।

18. समस्याएँ तब उत्पन्न हुई जब अपीलार्थी ने एक खुदरा दुकान के लिए दूसरे विज्ञापन के तहत एक और आवेदन किया। पुनः, दिनांक 02.01.2019 के अनुलग्नक-17 के रूप में प्रस्तुत एक प्रमाण पत्र द्वारा, प्राचार्य ने एक प्रमाणन किया जिसके साथ अपीलार्थी ने फिर से निर्भरता खंड का आह्वान किया। तुरंत, हमें यह देखना होगा कि निर्भरता खंड पर दूसरा आवंटन उचित नहीं होगा क्योंकि यह समानता खंड के खिलाफ काम करेगा; विशेष रूप से एक सार्वजनिक निकाय के खुदरा दुकानों के आवंटन में आजीविका प्रदान करना और परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु से हुए नुकसान की भरपाई करना है। हम इस पहलू पर आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरा आवंटन नहीं हुआ था।

19. निगम ने दिनांक 12.06.2019 के अनुलग्नक-16 के अनुसार पुनः स्पष्टीकरण मांगा और अपीलार्थी ने भी इस तरह के सत्यापन को फिर से किए जाने पर आपत्ति जताई। यह इस संदर्भ में था कि निगम द्वारा 18.06.2020 पर एक दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था ताकि यह जांच की जा सके कि सरकारी कर्मचारी को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है और क्या अपीलार्थी के पिता की मृत्यु वास्तव में दिनांक-23.09.1984 को सेवा के दौरान हो गई थी । दिनांक 20.06.2020 के जवाबी हलफनामे के साथ प्रस्तुत अनुलग्नक-डी के अनुसार डी. ई. ओ. से स्पष्टीकरण मांगा गया था। अनुलग्नक-ई दिनांक 06.08.2020 गठित समिति की रिपोर्ट है, जो डी. ई. ओ. के दिनांकित 08.07.2020 के एक

पत्र को संदर्भित करता है, जिसमें अपीलार्थी के पिता की मृत्यु की पुष्टि की गई है, जबकि वह 23.09.1984 पर सेवा में थे, लेकिन अनुलग्नक **VII** के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी पर बात नहीं की; जो अनुलग्नक निगम द्वारा जारी ब्रोशर से है, जिसमें केवल कार्यालय के प्रमुख या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की गई है जो एक अवर सचिव से कम नहीं है। कहा जाता है कि आगे की जांच पर डी. ई. ओ. ने के पत्र द्वारा जवाब दिया दिनांक 04.08.2020 और यह सूचित किया गया कि मृत्यु को प्रमाणित करने का उचित अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत होगी और 23.09.1984 पर, विषय विद्यालय रविवार होने के कारण बंद था। फिर से, हमें ध्यान देना होगा कि यह संचार अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के 36 साल बाद जारी किया गया था। डी. ई. ओ. जिस बात की बात करता है, वह भी एक मृत्यु प्रमाण पत्र है जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, जो निगम द्वारा मांगा गया प्रमाणन नहीं है। निगम को ब्रोशर में दिए गए अनुलग्नक-**VIII** के अनुसार प्रमाणन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए इसे कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है। समिति ने अपनी दिनांक 06.08.2020 की रिपोर्ट में पाया कि अपीलार्थी के पिता अपनी मृत्यु के समय विद्यालय की सेवा में थे और उनकी मृत्यु 23.09.1984 पर हुई जब वे अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे थे; उस दिन रविवार था। यह भी पाया गया कि कर्तव्य के निर्वहन में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डी. ई. ओ. उचित प्राधिकारी है क्योंकि यह वह कार्यालय है जो कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का रखरखाव करता है।

20. यहाँ, हम यह नोटिस करने से नहीं चूक सकते कि ये ऐसे तथ्य थे जिन्हें पहले आवेदन के समय ही सत्यापित किया जा सकता था और ऐसा नहीं किया गया। हमें अपीलकर्ता द्वारा कोई गलत प्रतिनिधित्व किए जाने का भी पता नहीं चला। यह कि अपीलकर्ता के पिता उनकी मृत्यु के समय सेवा में थे, विवादित नहीं है और न ही यह तथ्य विवादित है कि अपीलकर्ता उस शिक्षक से पैदा हुआ था जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हुई थी। समिति की अनुलग्नक-ई रिपोर्ट के कारण 29.08.2020 को पहला कारण बताओ सूचना जारी किया गया।

21. उपरोक्त रिट याचिका दिनांक 29.08.2020 के कारण बताओं सूचना के खिलाफ और क्रमशः प्रत्यर्थी संख्या 5 (प्राचार्य) और प्रत्यर्थी संख्या 4 (डि. ई. ओ.) द्वारा जारी दिनांकित 24.07.2020 और 04.08.2020 के आदेश को दरकिनार करने के लिए दायर की गई थी। फिर अनुलग्नक-13 द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने निगम द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दिया

कि बिहार सेवा संहिता के नियम 184 के अनुसार, छुट्टी की अवधि को भी कर्तव्य माना जाता है। इस संचार पर दिनांक 15.01.2022 के अनुलग्नक 27 में भरोसा किया गया था; जिसके कारण 29.08.2020 पर जारी किया गया पहला कारण बताओं सूचना वापस ले लिया गया।

22. यह तब था जब रिट याचिका लंबित थी, इसलिए निगम ने स्कूल द्वारा जारी प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए दिनांक 22.07.2022 (2023 का आई. ए. संख्या - 2) द्वारा फिर से डी.ई.ओ. से संपर्क किया। अनुलग्नक-21 के अनुसार, विद्यालय के प्रधानाचार्य ने दिनांक 27.08.2022 पर एक संचार जारी किया कि जारी किया गया प्रमाण पत्र हस्ताक्षर सत्यापन का था और निर्भरता प्रमाण पत्र नहीं है। प्रमाण पत्र की प्रति भी विद्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। यह स्पष्ट है कि आवेदक के हस्ताक्षर को अनुलग्नक-1 प्रमाण पत्र में प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया गया था । विद्यालय के अभिलेखों में केवल यह पाठ कि हस्ताक्षर सत्यापन किया गया था, इस तथ्य से विचलित नहीं करता है कि प्रमाण पत्र स्वयं अपीलार्थी को एक सहायक शिक्षक का पुत्र होने का संकेत देता है जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी; जिस तथ्य को हम दोहराते हैं, उस पर किसी ने विवाद नहीं किया है। जारी किया गया प्रमाण पत्र निगम द्वारा आवश्यक ब्रोशर में प्रदान किए गए अनुलग्नक **VIII** के अनुसार भी है। यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राचार्य ने इसे एक हस्ताक्षर सत्यापन के रूप में समझा जिसे अपीलार्थी के खिलाफ आरोप के रूप में नहीं लगाया जा सकता है, तो वह भी गलत निरूपण या जानबूझकर झूठ के रूप में। अपीलार्थी ने केवल अनुबंध-1 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले विज्ञापन के तहत आवेदन किया। भले ही अनुलग्नक-1 प्रमाण पत्र उस विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षर सत्यापन के रूप में जारी किया गया था जिसमें अपीलार्थी के पिता काम कर रहे थे; निगम ने वर्ष 2016 में अपीलार्थी को निर्भरता खंड का आह्वान करने में सक्षम बनाने के लिए इसे स्वीकार करना उचित समझा।

23. हम दोहराने के जोखिम पर दोहराते हैं कि निगम सत्यापित कर सकता था और आसानी से पता लगा सकता था कि मृत्यु रविवार को हुई थी और यह भी कि जब मृत्यु हुई थी, तो अपीलार्थी का जन्म नहीं हुआ था; जो अपीलार्थी की जन्म तिथि की तुलना करने से स्पष्ट होगा। जैसा कि अनुलग्रक-1 में प्रमाणित है। हम ऐसा मानते हैं, हमारी राय के बावजूद कि; रविवार को हुई मृत्यु की बहुत कम प्रासंगिकता है और अपीलार्थी का जन्म मृत्यु के समय नहीं हुआ था, इसका भी कोई परिणाम नहीं है। निगम द्वारा इस बिंदु पर कोई विवाद नहीं उठाया

जा सकता है कि अपीलार्थी ने कोई धोखाधड़ी की या कोई जालसाजी की। अनुलग्नक-1, जैसा कि हमने पाया, को हस्ताक्षर सत्यापन भी माना जा सकता है जिसमें हस्ताक्षरकर्ता के विवरण का उल्लेख किया गया है। निगम ने इसे खुली आँखों से स्वीकार किया; जो कि अपने स्वयं के विवरणिका में उपलब्ध अनुलग्नक **VIII** के रूप में था, जब सभी विवरण उसके सामने थे। अनुलग्नक-1 को जालसाजी नहीं कहा जा सकता है और न ही अपीलार्थी को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और योजना के तहत आवेदन करने में किसी धोखाधड़ी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सकता है। वहाँ अपीलार्थी द्वारा कोई दमनकारी सच्चाई या सुझाव गलत नहीं है; *न ही सत्य का दमन और न ही झूठ का सुझाव*। निगम अब झूठ के रूप में जो दावा करता है; जो वह नहीं है, उसे वर्ष 2016 में आर्यटन से पहले निगम द्वारा आसानी से सत्यापित किया जा सकता था।

24. निगम का दूसरा कारण बताओं सूचना दिनांक-07.10.2022, जो अनुलग्रक-22 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, 2014 के विज्ञापन के तहत वर्ष 2016 में किए गए खुदरा दुकान के आवंटन के संबंध में था। निर्भरता खंड, जैसा कि यहाँ ऊपर निकाला गया है, खंड 21 के साथ नोटिस में निकाला गया था, जो गलत जानकारी की बात करता है। यह इंगित किया गया था कि आवेदन के साथ एक नोटराइज्ड हलफनामा भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि आवेदन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी या घोषणा, यदि असत्य या गलत या झूठी पाई जाती है, तो निगम को आशय पत्र वापस लेने या डीलरशिप को समाप्त करने का अधिकार होगा और आवेदक को इस तरह की निकासी या समाप्ति के लिए निगम के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। फिर अपीलाथी द्वारा किए गए दूसरे आवेदन को भी रिट याचिका के रूप में संदर्भित किया गया था जो पटना के उच्च न्यायालय में लंबित थी; जिसमें चुनौती पहले कारण दस्सो नोटिस के खिलाफ थी, जिसे नोटिस वापस ले लिया गया था। 2019 के विज्ञापन के अनुसार दूसरी डीलरशिप के आवंटन की मांग करने वाली रिट याचिका को 5000/- रुपये की लागत के साथ वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया। यह भी कहा गया है कि रिट याचिका खारिज होने के बाद भी, अपीलकर्ता वर्ष 2019 में विज्ञापित डीलरशिप के संबंध में आशय पत्र जारी करने के लिए निगम के विभिन्न प्राधिकरणों से संपर्क कर रहा था।

25. कारण बताओं सूचना का सार फिर से अपीलार्थी के जन्म प्रमाण पत्र और उत्क्रमित माध्यिक विद्यालय मनियारपुर द्वारा जारी किया गया। दोनों की तुलना करने पर, यह पाया गया कि अपीलार्थी के पिता का निधन 23.09.1984 पर अपीलार्थी के जन्म से पहले ही हो गया था; जो 13.01.1985 पर था। यह राय दी गई थी कि जहाँ तक अपीलार्थी ने खुद को अपने पिता का आश्रित बताया है, एक विरोधाभास है, जिसे बहुत गंभीर प्रकृति का बताया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नियुक्ति पत्र वापस ले लिया गया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा उत्क्रमित माध्यिक विद्यालय मनियारपुर के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी एक जाली-सह-नकली सी. सी. आई. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

26. अपीलार्थी ने 07.10.2022 को जारी दूसरे कारण बताओ सूचना को चुनौती देते हुए 2022 के आई.ए संख्या-2 दायर किया। अपीलार्थी ने प्राचार्य के दिनांकित 27.08.2022 के पत्र को रद्द करने के संबंध में अन्य प्रार्थनाएं भी कीं और मूल दस्तावेजों और स्कूल के अभिलेखों को प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की। 2022 का आई. ए. संख्या 3 प्रत्यर्थियों द्वारा इस आधार पर रिट याचिका के निपटारे की मांग करते हुए दायर किया गया था कि पहला कारण बताएँ नोटिस दिनांक 29.08.2020; जिसे रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, उसे वापस ले लिया गया।

27. हम यह देखने के बिना नहीं रह सकते कि प्रतिवादी-निगम द्वारा की गई इस तरह की प्रार्थना दुर्भावनापूर्ण है, विशेष रूप से जब उस समय, समान तथ्यों के सेट पर, एक अन्य कारण सूचना जारी की गई थी; जिसे रिट याचिका में एक अंतर्वर्ती आवेदन के माध्यम से चुनौती देने की भी मांग की गई थी। अपीलार्थी द्वारा दायर 2022 की आई. ए. संख्या 2 को अनुमति दी गई थी और रिट याचिका के निपटारे के लिए दायर 2022 की आई. ए. संख्या 3 पर, जाहिर है, विचार नहीं किया गया था। जबकि कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने का निर्देश था, 09.02.2023 दिनांकित एक संचार द्वारा, अपीलार्थी के खुदरा आउटलेट को समाप्त कर दिया गया था, जिसे 2023 आई. ए. संख्या-5 में चुनौती दी गई थी। 2023 का आई. ए. नंबर 4 भी 10 वें प्रतिवादी को उसकी व्यक्तिगत क्षमता में शामिल करने और अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर किया गया था। निगम ने यह भी दावा करने का प्रयास किया कि एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 13.02.2023 के आदेश के अनुसरण में कोई अंतरिम स्थगन आदेश लागू नहीं था। इसके अनुसरण में, रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया और

एक नया कारण बताओं सूचना जारी करने की स्वतंत्रता छोड़ दी गई। अब तक, एक तीसरा कारण बताओं सूचना जारी किया गया है जो 07.03.2024 दिनांकित है, जिसे अपील में पूरक हलफनामे के साथ अनुलग्नक-ए/2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

28. अब जारी किए गए तीसरे कारण बताओ सूचना में यह भी आरोप लगाया गया है कि 2014 में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच से पता चलता है कि अपीलकर्ता के पिता की मृत्यु 23.09.1984 को हुई थी, जिस तारीख को अपीलकर्ता का जन्म नहीं हुआ था और इस बात में तथ्यात्मक विरोधाभास है कि अपीलकर्ता दिवंगत पिता पर कैसे आश्रित हो सकता है यह भी आरोप लगाया गया है कि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मनियारपुर के प्राचार्य द्वारा कथित रूप से जारी एक जाली-सह-नकली सी. सी. आई. प्रमाण पत्र, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे केवल हस्ताक्षर सत्यापन बताया गया था और निर्भरता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में नहीं। यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रधानाध्यापक ने अब संकेत दिया है कि अनुमंडल अधिकारी निर्भरता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। तीसरे कारण बताओ नोटिस के अनुसार, ये आरोप गंभीर प्रकृति के पाए गए और मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है।

29. वर्तमान कारण बताओ सूचना में लगाए गए आरोप प्रथम और द्वितीय कारण बताओ सूचना में लगाए गए आरोपों के समान ही हैं। हमने पहले ही पाया है कि अपीलकर्ता के जन्म से पहले पिता की मृत्यु होने पर भी उसे आश्रित के दर्जे से वंचित नहीं किया जा सकता; जो कि निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया एक बेतुका प्रस्ताव है; निगम एक सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है जिसके पास उपलब्ध सर्वोत्तम कानूनी सलाह तक पहुँच है। इसके अलावा यह आरोप कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र जाली है, बिल्कुल भी मान्य नहीं है। जैसा कि हमने पाया, भले ही हम यह मान लें कि यह केवल हस्ताक्षर सत्यापन के लिए जारी किया गया था; जो कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को देखते हुए एक संभावित दृष्टिकोण है, यह निगम द्वारा अपेक्षित प्रारूप में जारी किया गया है। अपीलकर्ता के हस्ताक्षर को स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा सत्यापित किया गया है, जिसे सत्यापित किया गया है। रिट याचिका में अनुलग्नक-1 के रूप में प्रस्तुत उक्त प्रमाण पत्र, निश्चित रूप से, अभी तक स्कूल के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इससे यह संकेत नहीं मिलता कि जो प्रस्तुत किया गया है वह फर्जी प्रमाण पत्र है या धोखाधड़ी वाला है। प्रमाण पत्र में बताए गए तथ्य निर्विवाद हैं और विवादित नहीं हैं। अपीलकर्ता दिवाकर झा का पुत्र है, जो

उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनियारपुर में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत था और शिक्षक की मृत्यु 23.09.1984 को हो गई थी।

30. निगम की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील बताते हैं कि प्रमाण पत्र में यह कथन कि अपीलार्थी विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार पुत्र और आश्रित था, सही नहीं हो सकता है क्योंकि मृत्यु की तारीख को अपीलार्थी का जन्म नहीं हुआ था। हम दोहराते हैं कि अपीलार्थी का जन्म पिता की मृत्यु के चार महीने बाद हुआ था और प्रमाण पत्र वर्ष 2014 में, पिता की मृत्यु के लगभग 30 साल बाद जारी किया गया था। अपीलार्थी को विद्यालय के अभिलेखों में आश्रित दिखाया गया होगा; जो सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए किए गए आवेदनों से भी होगा। प्रमाणपत्र में कुछ भी संदिग्ध नहीं है जिसमें अपीलार्थी को मृत व्यक्ति के बेटे और आश्रित के रूप में दिखाया गया है; क्योंकि यह निर्विवाद । इसके अलावा, जैसा कि हमने पहले देखा, आवंटन दिए जाने से पहले वर्ष 2016 में ही निगम को इन तथ्यों का सत्यापन करने से कोई नहीं रोक सका था।

31. हमें नहीं लगता कि अपीलार्थी द्वारा कोई गलत अभ्यावेदन किया गया है और प्रमाण पत्र को भी धोखाधडी से प्राप्त प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जा सकता है। जैसा कि हमने देखा, अपीलार्थी के पास दूसरे आवंटन के लिए मामला नहीं हो सकता है, लेकिन उसका पहला आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता है। हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश को दलीलों पर विचार करना चाहिए था और न कि केवल अपीलार्थी को एक और कारण बताओं सूचना पर छोड़ देना चाहिए था। अपीलार्थी ने पहले कारण बताओं सूचना को चुनौती दी थी, जिसे निगम द्वारा वापस ले लिया गया था और फिर से उसी तथ्यों के आधार पर दूसरा कारण बताओं सूचना जारी किया गया था; जिसे भी वापस ले लिया गया है। अब, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के बाद, वर्ष 2016 में आवंटित खुदरा दुकान को स्पष्ट रूप से अस्थिर और बेतुके आधारों पर रद्द करने के लिए तथ्यों के उसी समूह पर एक तीसरा कारणदर्शक नोटिस फिर से जारी किया गया है।

32. आम तौर पर, हम कारण बताओ नोटिस में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन वर्तमान मामले में कार्यवाही स्पष्ट रूप से मनमानी है और निगम की कार्रवाई भी प्रतिशोधात्मक है; अपीलकर्ता द्वारा विभिन्न अधिकारियों के समक्ष की गई शिकायतों के कारण, रिट याचिका में

अपमानजनक रूप से संदर्भित और तर्कों में उपहासपूर्ण ढंग से आग्रह किया गया है। हमने यह भी देखा है कि जब उन्हीं तथ्यों पर दूसरा कारण बताओ नोटिस लंबित था, तब भी निगम ने रिट याचिका के निपटान की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। हम पाते हैं कि निगम ने एक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के अनुचित तरीके से काम किया है।

33. उपरोक्त तर्क पर, हम जारी किए गए कारण बताओं सूचना में हस्तक्षेप करते हैं, जैसा कि अपील में प्रस्तुत किया गया है। कारण बताओं सूचना में बताए गए तथ्यों के आधार पर वर्ष 2016 में किए गए आवंटन को रद्द नहीं किया जा सकता है और आरोप टिकाऊ नहीं हैं। हम विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार करते हैं और निगम को वर्ष 2016 के आवंटन के संबंध में कोई भी आगे का कदम उठाने से रोकते हैं क्योंकि या तो निर्भरता उचित नहीं है या निर्भरता का प्रमाण पत्र वैध नहीं है।

34. रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी निगम के प्रतिशोधात्मक रवैये के कारण; जिसकी हम सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन से कम से कम उम्मीद करते हैं, हम एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हैं, जिसे अपीलकर्ता को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। यदि राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अपीलकर्ता अपीलकर्ता को आपूर्ति किए गए पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य से इसे समायोजित करने का हकदार होगा।

35. तदनुसार आदेश दिया।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

मैं सहमत हूँ।

हरीश कुमार, न्यायमूर्ति

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

अनुस्का/सुजीत

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।